विशेषज्ञ टिप्पणी

यह बजट वैश्विक अनिश्चितताओं तथा परिवर्तित होते परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह बजट मात्र सरकारी व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास रणनीति, नीति प्राथमिकताओं तथा दीर्घकालिक आर्थिक दिशा का एक समग्र प्रतिबिंब भी है। वर्तमान परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी अवसंरचना तथा तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। दीर्घकाल तक प्रदेश का आर्थिक विकास मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आधारित रहा है। उद्योग, गन्ना उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, एमएसएमई क्षेत्र तथा दिल्ली–एनसीआर से भौगोलिक निकटता के कारण यह क्षेत्र राज्य का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा। प्रश्न है बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र विकास प्रक्रिया में समान रूप से सहभागी बना पा रहे है?

– **प्रो. दिनेश कुमार**, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एमएसएमई के लिए घोषित योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

पश्चिम के 'जेवर' से चमकेगा प्रदेश, 'उड़ान' भरेगी अर्थव्यवस्था

रवि प्रकाश तिवारी • जागरण

मेरठ: ग्रेटर नोएडा के जेवर में स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश को अर्थव्यवस्था को भी चमकाने में प्रतिभागी बनेगा। इसके साथ ही चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एमएसएमई का गढ़ है, इस लिहाज से इस बजट का बड़ा हिस्सा पश्चिम के भी हाथ लगेगा। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार ने भी एमएसएमई पर विशेष फोकस करते हुए बजट में 3822 करोड़ का प्रविधान किया है।

राज्य बजट में जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ आवंटित करने, रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने की घोषणा हुई है। यहां से जब पश्चिम उप्र की यात्रा पर बढ़ेंगे तो कुछ ही दूरी पर स्थित खुर्जा और दादरी मिलते हैं। ये वे स्थान हैं, जहां तेज गति से दौड़ने वाली मालगाड़ी के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर यानी दोनों कारिडोर मिल रहे हैं। बुलंदशहर वह हिस्सा बनकर उभर रहा है, जहां पर नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जाना है और इसी जिले में नोएडा का नया एक्सटेंशन विकसित किया जाना है।

औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़े, इसके लिए औद्योगिक आस्थान क्षेत्रों के विकास, संवर्धन के लिए अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इस बार मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ जैसे जिलों की झोली भरेगी। पिछले बजट में मेरठ को लगभग 200 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। शामली से गोरखपुर तक नया एक्सप्रेसवे बनना है, जिसका सर्वे किया जा रहा है। इन सबको देखें तो पश्चिम उप्र को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से सीधे जोड़ते हुए आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए नवें सेंटर के रूप में विकसित हो रहे मेरठ में प्रदेश की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत टाउनशिप विकसित की जा रही है। देश की पहली सेमी हाईस्पीड रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत को इसी शहर तक पहुंचाया गया। यहीं पर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। सत्र प्रारंभ हो चुके हैं, 700 करोड़ से कैंपस निर्माण अगस्त तक पूरा होना है। गंगा एक्सप्रेसवे यहीं से शुरू हो रहा है और इसके किनारे बिजौली में भारी उद्योगों के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। अब इसी एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने का संकल्प फिर दोहराया गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फंड के तहत मेरठ समेत तीन शहरों के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रविधान है।

बजट की बड़ी बातें

- जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 750 करोड़ का आवंटन
- बुलंदशहर में पहली औद्योगिक योजना की घोषणा
- इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में मेरठ को मिल सकते 250 करोड़
- अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ को मिलेगा धन

3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना भुगतान प्राप्त होगा किसानों को

700 करोड़ से होगा पहले खेल विश्वविद्यालय में कैंपस का निर्माण

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट • जागरण आर्काइव

गन्ना भुगतान के आंकड़े भुनाने की कोशिश

पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि से किसानों को लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना भुगतान प्राप्त होगा। गन्ना किसानों को साधने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने इसका उल्लेख भी मजबूती से किया। योगी सरकार ने अब तक तीन लाख चार हजार करोड़ से अधिक का भुगतान कराया है।

बजट से ब्रज में बहार, फिर बाकी रह गई यमुना की बात

अवधेश माहेश्वरी • जागरण

आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रज रज पसंद है। ऐसे में प्रदेश के बजट में ब्रज के लिए तो बहार है, परंतु यमुना को सूखी धार है। मथुरा के पर्यटन को आगे ले जाने के लिए बजट में बड़ा पुश दिया है। बड़े विकास को ही 692 करोड़ रुपये का प्रविधान है। इससे वहां तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित होगा।

वृंदावन के भार को देखते हुए अब कृष्ण प्रेमी नंदगांव, गोवर्धन और बरसाना की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऐसे वहां की जरूरत को देखते हुए 86 किमी सड़क को चार लेन करने के लिए 392 करोड़ रुपये मिले हैं। इस सड़क के चौड़ीकरण से इन तीनों जगह पर्यटकों के पहुंचने में बहुत सुविधा रहेगी। ब्रज के तीर्थ स्थलों के विकास को 130 करोड़ रुपये हैं, ऐसे में यहां लगातार सुधार किया जा सकता है। तीर्थयात्रियों की अन्य सुविधाओं को भी लगभग 20 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। योगी सरकार ने जिस तरह ब्रज में पर्यटन पर ध्यान दिया है, उसका ही परिणाम है कि पिछले वर्ष यहां यात्रियों की संख्या नौ करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपये मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को आधारभूत ढांचा सुधार को मिलेंगे। इससे पर्यटकों के लिए सुविधा ही बढ़ेंगी। बजट में ब्रज में बहार के साथ यमुना की बात बाकी रह गई है। इस पर प्रश्न यह है कि यमुना को शुद्ध जलधार बिना क्या ब्रज बचेगा? शायद नहीं, यमुना में ब्रज की शक्ति और भक्ति दोनों समाई हैं। उसकी शुद्धता को प्रविधान होना चाहिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले वर्ष के प्रारंभ में चुनावी परीक्षा को जाना है, ऐसे में तो और भी खयाल रखना चाहिए था।

मथुरा में तीर्थयात्रियों के लिए 692 करोड़ से होगा आधारभूत ढांचा विकसित, वृंदावन में 86 किमी सड़क होगी चार लेन